

खबर संक्षेप

13 जुलाई से शुरू होगा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण

मण्डला। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित यह विशेष अभियान आगामी 13 जुलाई से 18 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य ध्येय दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मध्यप्रदेश की समृद्धि के संकल्प को साकार करना है। अभियान के दौरान विभाग के विशेषज्ञ और मैदानी अमला सीधे पशुपालकों से संपर्क करेंगे और उन्हें डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभदायक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों से अवगत कराएंगे। अभियान के दौरान स्थानीय मवेशियों की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय। मवेशियों के लिए संतुलित आहार, हरा चारा प्रबंधन और पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीयों। पशुओं को विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण के प्रति जागरूकता। उन्नत तकनीक के माध्यम से बछड़ियों के जन्म को बढ़ावा देने की तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी, जिससे भविष्य में दुग्ध उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सके। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जिले के सभी पशुपालकों और किसानों से अपील की है कि वे 13 से 18 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और शासकीय योजनाओं एवं आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं।

*** जनप्रतिनिधियों ने बताई सुरक्षा और आर्थिक बोझ की समस्या।**

हरिभूमि न्यूज़ ॥ मण्डला

जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत कटरा आज व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। पंचायत क्षेत्र में अनेक निजी संस्थान, अस्पताल और विभिन्न

भारी ट्रैफिक से गुजरकर स्कूल पहुंचने को मजबूर छात्र

कटरा में संदीपनी विद्यालय खोलने की मांग



विभागों के शासकीय छात्रावास संचालित हैं। इसके बावजूद यहां माध्यमिक स्तर के बाद शासकीय हाईस्कूल की सुविधा नहीं होने से छात्रावासों में रहने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों को प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर दूर शहर स्थित शासकीय हाई स्कूलों तक जाना पड़ता है।

जानकारी के

अनुसार कटरा क्षेत्र में लगभग 4 से 5 शासकीय छात्रावास संचालित हैं,



जिनमें करीब 3 से 4 सौ विद्यार्थी निवास करते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए इन विद्यार्थियों को ऑटो या साइकिल के माध्यम से प्रतिदिन मंडला-जबलपुर मार्ग से आवागमन करना पड़ता है। इस दौरान विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना रहता है।

ग्राम पंचायत कटरा के सरपंच हरि शंकर मरावी ने बताया कि पंचायत में वर्तमान में केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला संचालित है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को मजबूरी में शहर जाना पड़ता है। अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, इसलिए प्रतिदिन का आवागमन उनके लिए आर्थिक और सुरक्षा दोनों दृष्टि से बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया की

छात्रावासों के पीछे पर्याप्त भूमि है जहां विद्यालय बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि शासन एवं संबंधित विभाग कटरा में संदीपनी विद्यालय खोल दे तो छात्रावासों में रहने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा मिल सकेगी। इससे बच्चों का समय और धन दोनों बचेंगे तथा व्यस्त मंडला-जबलपुर मार्ग पर रोजाना होने वाले जोखिम से भी उन्हें राहत मिलेगी।

क्षेत्रवासियों ने भी शासन से मांग की है कि जिस प्रकार शहर के अधिकांश शासकीय छात्रावास इसी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कटरा में हायर सेकेंडरी स्कूल की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जाए, ताकि गरीब एवं ग्रामीण विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सके।

स्वर्गीय विनोद परस्ते के परिवार को सचिवों द्वारा 10000 की राशि दी गई



नारायणगंज। कल दिनांक 05/07/2026 को ग्राम पंचायत देवहार जनपद पंचायत नारायणगंज के रोजगार सहायक विनोद परस्ते जी का देहांत हो गया। श्री परस्ते के अंतिम संस्कार के समय ग्राम के लोगों के साथ-साथ क्षेत्र के पंचायत सचिव भी पहुंचे जिन्होंने मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुये अपनी ओर से मिलजुलकर 10000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। विडम्बना है कि किसी भी ग्रामीण की अंत्येष्टी के लिये 5000 रुपये की सहायता राशि प्रावधान है लेकिन पंचायत में काम कर रहे रोजगार सहायक के साथ यदि इस तरह की विपदा आती है तो उसके लिये किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है और यही कारण है कि सचिव मिलकर नगद 10000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की।

गांव-गांव गली हाइवे के होटलों में बिक रही शराब

हरिभूमि न्यूज़ ॥ मण्डला/भुआबिछिया

नगर सहित पूरे भुआबिछिया क्षेत्र में खुलेआम फलफूल रहा विदेशी और देशी शराब माफियाओं का कारोबार, महंगे दामों में ठेका लेने के बाद ठेकेदार के गुगों ने आस पास ग्रामों की होटल चाय पान के टपरो में शहर से लेकर ग्रामों तक खुलेआम शराब पिलाई जा रही जिससे युवा वर्ग से लेकर ग्रामों के अनेक वर्ग के लोग इससे प्रभावित हैं, ग्रामों में आज भी महिलाएं शराब का विरोध कर रही आज भी अनेक ग्राम ऐसे हैं जहां शराब पूरी तरह बंद है, मगर शराब माफियाओं के गुगों प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखा गांव गांव शराब गाड़ियों से भेज कर वहां की छोटी छोटी दुकानों होटलों में कमीशन का लालच देकर शराब बिकवाई जा रही, नगर को ही ले ले तो NH 30 हाईवे के किनारे ऊमरवाड़ा ओरई होटलों में देर रात तक शराब परोसी जा रही है, मगर मजाल है कि आबकारी विभाग सहित प्रशासन इस पर कोई



कार्यवाही करे। अनेक शराब प्रेमियों से शराब दुकान में होते विवाद की पिछले ठेके से भी ज्यादा दामों क्यों बेची जा रही शराब कुछ लोगों ने विरोध किया तो माफियाओ ने धमका दिया और भगा दिया जाता है और नहीं तो मारपीट करने पर उतारू हो जाते है। ग्रामीणों का कहना है कि कई स्थानों पर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं की गई है। इसके कारण शराब की बिक्री निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर बेची जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों का आरोप है कि उपभोक्ताओं से मनमाने दाम

वसूलकर अवैध कमाई की जा रही है। आबकारी नियमों के अनुसार, प्रत्येक अधिकृत शराब दुकान पर शासन द्वारा स्वीकृत रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य है, ताकि उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि की वसूली न हो सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था के पालन को लेकर अनेको सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने आबकारी विभाग एवं जिला प्रशासन से अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।

9 मोबाइल एवं चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

हरिभूमि न्यूज़ ॥ मण्डला

पुलिस अधीक्षक मंडला राजेश रघुवंशी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा तथा एसडीओपी निवास पी.एस. बालरे के मार्गदर्शन में चौकी मनेरी पुलिस ने मोबाइल एवं मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का सफल खुलासा करते हुए एक शक्ति चोर को गिरफ्तार कर लगभग 2.70 लाख रुपये मूल्य की चोरी गई संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

गत लगभग 15 दिनों से चौकी मनेरी क्षेत्र में लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं। इसी दौरान दिनांक 03.07.2026 को ग्राम मेंडी निवासी संजय उर्फ भूरा बर्मन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रात्रि में परिवार के सो जाने के बाद अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुसकर स्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक MP 20 NQ 7928 चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर शिवम मरावी पिता प्रताप मरावी, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम खुख, थाना कुंडम, जिला जबलपुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।



पूछताछ में आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि गत 15 दिनों में मनेरी क्षेत्र में हुई मोबाइल चोरी की घटनाओं को भी उसी ने अंजाम दिया था।

आरोपी की निशानदेही पर चोरी गई स्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल एवं विभिन्न कंपनियों के 09 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 2,70,000 रुपये है। बरामद मोबाइलों में थाना बरेला, जिला जबलपुर क्षेत्र से चोरी हुए मोबाइल भी शामिल हैं। आरोपी एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व से थाना बरेला में 03 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी

से क्षेत्र में हुई कई संपत्ति संबंधी चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है।

गिरफ्तार आरोपियों में शिवम मरावी पिता प्रताप मरावी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खुख, थाना कुंडम, जिला जबलपुर शामिल रहा। जप्त सामग्री में स्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक MP 20 NQ 7928, -09 स्मार्ट मोबाइल फोन, (विभिन्न कंपनियों के) -कुल अनुमानित कीमत : 2,70,000 रुपये की जप्ती बनी। उक्त कार्रवाई में चौकी प्रभारी मनेरी उप निरीक्षक शशांक शुक्ला, सहायक उप निरीक्षक साधु सिंह, प्रधान आरक्षक बलिराम, प्रधान आरक्षक अरविंद, आरक्षक आनंद कोरी, मुकेश शांडिल्य शामिल रहे।

समस्या

सड़क, बिजली, पानी एवं मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं का टोटा।

सुविधाओं को तरसते मुख्यालय मवई के ग्रामवासी

*** बैंकिंग सर्वर ठप्प होने से परेशान ग्रामीणजन।**

हरिभूमि न्यूज़ ॥ मण्डला/मवई

मामला जिले के अंतिम छोर मै बसे वनांचल मवई का है।एक ऐसा मुख्यालय जहां की विद्युत सप्लाई मोबाइल नेटवर्क, नल जल योजना सड़क मार्ग एवं अन्य मूलभूत सुविधाये भगवान के भरोसे चल रही है। ग्रामवासी बिजली पानी सड़क ओर नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे है। एक ओर सरकार डिजिटल इंडिया का सपना लोगो को दिखा रही है वहीं नेटवर्क कंपनिया डिजिटल इंडिया के सपने को पलीता लगा रहे है। विद्युत सप्लाई बंद होते ही मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी की उदासीनता से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना ठप्प पड़ी हुई है। मवई कूड़ेला मार्ग की घटिया निर्माण कार्य और अधूरी पुलिस का डायवर्सन बह जाने से सैकड़ों गांव



का मवई मुख्यालय से संपर्क टूट गया। क्या जिला प्रशासन ओर अपने आप को जनता का हितैषी कहने वाले जनप्रतिनिधियों को इन समस्याओं की जानकारी नहीं? या जानबूझ कर धृतराष्ट्र की तरह अपनी आँखें बंद करके बैठे है। जिनका जवाब मिलना शायद मुश्किल है।

बारिश में ही खुली विद्युत विभाग की पोल

बारिश का मौसम शुरू होते ही विद्युत

विभाग की पोल खुलने लगी है। थोड़ी सी ही बारिश मै फाल्ट के नाम पर दिन रात विद्युत बंद कर दी जाती है। जिससे आम जनजीवन प्रभाव पड़ रहा है एवं घरेलू शासकीय एवं व्यावसायिक कार्यप्रभावित हो रहे है।

विद्युत बंद होते ही नेटवर्क गोल

थोड़े ही बारिश मै विद्युत सप्लाई बंद होते ही नेटवर्क बंद कर दिया जाता है। जिससे बैंकिंग सुविधाएं, लोगों



का आपातकालीन संपर्क टूट जाता है। लोग अपने ही पैसे एवं अन्य कार्य के लिए बैंकिंग सर्वर धप्प होने के कारण बैंक के चक्कर काटने को मजबूर है।

डायवर्सन बह जाने से आवागमन प्रभावित

कूड़ेला-मवई मार्ग मै निर्माणाधीन पुलिसा के पास बनाया गया डायवर्सन बारिश होते ही बह गया जिससे आवागमन बाधित हो गया।और सैकड़ों गांव का मवई

मुख्यालय से संपर्क टूट गया।

ग्रामवासियों ने बढ़ रही नाराजगी

ठप्प पड़ी विद्युत सप्लाई,मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम घटिया सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं ना मिलने से ग्रामवासियों का प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। लोगो के द्वारा जल्द ही इन मूलभूत सुविधाओं का स्थाई समाधान करने की मांग की जा रही है।

बिछिया में अवैध शराब का बड़ा जखीरा जब्त



*** दो आरोपी न्यायिक अमिरक्षा में भेजे गए।**

हरिभूमि न्यूज़ ॥ मण्डला

जिला आबकारी अधिकारी तथा प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती शैली सैयाम के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने बिछिया वृत्त में अवैध शराब के विरुद्ध सघन कार्रवाई करते हुए एक घर से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की।

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी दल ने वार्ड क्रमांक-15, परमाही टोला, बिछिया स्थित एक मकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान घर में मौजूद सुरेंद्र यादव (48 वर्ष) एवं रवि यादव (21 वर्ष) की उपस्थिति में विधिवत जांच की गई। कमरे में पलंग के नीचे छिपाकर रखे गए देसी प्लेन मदिरा के 7 कार्टून बरामद हुए। प्रत्येक कार्टून में 50-50 नग मदिरा होने से कुल 350 नग देसी प्लेन शराब, जिसकी मात्रा 63 बल्क लीटर है, जब्त की

गई। आरोपियों से मदिरा के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। धारण क्षमता से अधिक मदिरा का संग्रहण एवं विक्रय के उद्देश्य से रखने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त मदिरा की अनुमानित कीमत लगभग '35 हजार रुपये' बताई गई है।

कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक सर्वेश नागवंशी, प्रधान आरक्षक हरे सिंह उड़के तथा आरक्षक रघुनाथ उड़के, महेश पटेल, कन्हैया उड़के सहित समस्त आबकारी अमला उपस्थित रहा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।



ख़बर संक्षेप

खुलरी सहित क्षेत्र के गांवों में बिजली की अघोषित कटौती के चलते हो रहे लोग परेशान

हरिभूमि न्यूज/खुलरी। जहां एक ओर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली कटौती न करने के लिये लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों के निर्देश दिये जा रहे हैं। मगर इसके बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते लोगों के अघोषित बिजली कटौती का सामना करने के लिये मजबूर होते हुये देखा जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो इस समय चल रहे बारिश के मौसम में हो रही बिजली कटौती के चलते जहां लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होने के साथ साथ निकल रहे जहरीले कीड़ों का शिकार होने से नही बच पा रहे हैं। इस प्रकार से खुलरी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों में हो रही बिजली की अघोषित कटौती के चलते लोगो का बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ते हुये दिखाई देने लगा है। क्योंकि रात के समय होने वाली इस बिजली कटौती के संबंध में जब अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो उनके द्वारा अपना फोन उठाया भी उचित नही समझा जाता है, इस बात की सच्चाई बीते दिवस उस समय देखने मिली जब खुलरी स्थित पावर हाऊस तक तो बिजली सप्लाई चल रही थी, मगर खुलरी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों की आवाक बिजली बंद रहने के कारण सारी रात लोगों को अंधेरे में अपनी रात काटने के लिये जलबूरे होना पड़ा, इस प्रकार से बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही तानाशाही पूर्ण कार्य प्रणाली के चलते प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को बिजली उपलब्ध कराने में असफल रहने वाली 15 वर्ष पहले की छबि को याद दिलाने में कोई कसर नही छोड़ी जा रही है?

कहां गायब हो गई कुछ साल पहले शुरू की गई ग्रेन बैंक की योजना

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। जहां एक ओर प्रदेश से लेकर केन्द्र सरकार द्वारा लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं का शुभारंभ तो किया जाता है। मगर अधिकांश योजनाएं मात्र औपचारिकता तक ही सीमित होकर रहे जाती है...? कुछ इसी प्रकार से कुछ वर्ष पहले शुभारंभ हुई ग्रेन बैंक योजना का हाल जान पड़ रहा है। बताया जाता है कि बीते हुये कुछ वर्ष पहले यानि की 9 मई 2013 को समीपस्थ साईंखेड़ा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाली खेरी में जिला प्रशासन का नवाचार ग्रेन बैंक अनाज कोष का शुभारंभ तत्कालीन जिला कलेक्टर संजीव सिंह, तत्कालीन जिला पंचायत साईंओ दीपक सक्सेना व तत्कालीन जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पारथ सिंह गुजर की उपस्थिति में बडे ही जोर शोर के साथ शुभारंभ किया गया था। वहीं इसकी लेकर बताया गया था कि इस ग्रेन बैंक अनाज कोष की स्थापना किये जाने का उद्देश्य ग्राम पंचायतों की ग्राम के लोगों के छोटे-छोटे सहयोग से स्थान्मन्त्री बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे लोग जनमानोंदारी के रूप में स्वेच्छिक दान अनाज के रूप में ग्रेन बैंक को प्रदान करेंगे, जिससे ग्राम का विकास होगा। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को उस समय जानकारी देते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर संजीव सिंह ने कहा था कि हमारे प्रदेश में ग्रेन बैंक कई जिलों में खोले जा रहे है, ग्रेन बैंक खोले जाने के पीछे मूल रूप से जनमानोंदारी की भावना है। वहीं कई ग्रामों में जनमानोंदारी की भावना से गांव की सरकारों को बहुत ही खुबसूरती से सवारा गया है, गांव के लोगों के द्वारा जो स्वेच्छिक दान अनाज के रूप में प्राप्त होगा उसे राशि में कन्वर्ट कर जो राशि प्राप्त होगी उसके 100 गुना कर सरकार गांव के विकास में राशि प्रदान करेगी। मगर इस बैंक के शुभारंभ होने के बाद आज तक इस बैंक के बारे में न तो लोगों के पास कोई जानकारी प्राप्त हुई और यहां तक बताया जात रहा है कि यह बैंक विकास मात्र एक गांव में शुभारंभ होने के बाद स्थिति सी हो जाने से यह जान पड़ रहा है कि मात्र औपचारिकता तक ही सीमित हो गई है।

सांझा चूल्हा कार्यक्रम ने गांवों में तोड़ा दम, बच्चे खिचड़ी भरोसे चला रहे अपना काम

हरिभूमि न्यूज/ साईंखेड़ा। साझा चूल्हा पोषण आहार कार्यक्रम यहाँ एक औपचारिकता बन कर रह गया है। वहीं क्षेत्र के कई गांवों में इस योजना ने दम तोड़ दिया है। गांवों में जाकर देखा जावे तो वहां पर न तो मौजूद है अनुसार मौजम तैयार हा रहा है और न ही बच्चों को दिया जा रहा है और न ही साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है? सरकार ने ग्रामीण स्कूलों के बच्चों और महिला एवं बाल विकास विभाग की आँगनवाडियों के बच्चों के लिए एक ही चूल्हे पर ताजा और पौष्टिक आहार देने की योजना को लागू तो किया गया है। किन्तु योजना का समुचित लाभ बच्चों को नही मिल रहा है।

मानसून की मेहरबानी, किसानों के चेहरों पर खुशी की झलक, धान रोपने की तैयारियों में जुटा क्षेत्र का अन्नदाता



हरिभूमि न्यूज/ सालीचौका। जहां एक ओर अन्नदाताओं को अपनी फसल का बाजीब दाम नही मिलने के कारण फसल पैदा करने में लगाई गई लागत खड़ी नही हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति भी अब अन्नदाताओं को धूखा देने में पीछे नही रहने के चलते माटी पुत्र लगातार टूटते चला जा रहा है। मगर इसके बाद भी क्षेत्र का किसान प्रकृति की मार झेलते हुये किसी भी प्रकार से अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाने में जुटा हुआ देखा जा रहा है। क्योंकि प्रकृति जिस तरह धोखा दे रही थी उसके चलते माटी पुत्र को टूटते हुये देखा जाने लगा था। क्षेत्र का अन्नदाता प्रकृति की मार झेल रहा है तो दूसरी ओर सरकार भी उनके भरोसे पर जिस तरह चोट दे देती है उसके चलते किसानों की आंखों में आंसू आने से नही चूक पाते है...? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस वर्ष भी देखने मिल चुकी है। क्योंकि हर साल जिस तरह किसानों द्वारा गर्मी के दिनों में पैदा करने वाले मूंग फसल को सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदते हुये किसानों को मदद की जा रही थी। उसी के चलते इस वर्ष भी किसानों को पूरा भरोसा था कि सरकार द्वारा उनकी मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदा जावेगा। इसी सोच के चलते क्षेत्र में गर्मी मूंग के रकबा में इजाफा हुआ था और जब किसानों की मूंग फसल कटकर तैयार हुई तो सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग फसल को खरीदने के लिये के लिये जो नियम बनाते हुये घोषणा की गई है कि किसानों की समर्थन मूल्य पर मात्र 25 प्रतिशत ही मूंग

परेशानियों से जुड़ा रहे क्षेत्रवासियों को अनेक संकटों से करना पड़ रहा है सामना, शासन की योजना पर सवाल ..

हरिभूमि न्यूज/सालीचौका। भले ही सरकार द्वारा आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाते हुए लगातार विकास के बादे किये जा रहे है, मगर यदि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सच्चाई पर जाया जावे तो वह योजनाएं कागजो तक ही सीमित नजर आने से नही चूक रहे है तथा इसी के चलते शासन द्वारा चलाई जा रही संपूर्ण योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगने से नही चूक रहा है? इस बात की सच्चाई जनपद पंचायत चीचली व साईंखेड़ा क्षेत्र के तहत आने वाले अनेक ग्रामों में ग्रामीणजन मूल भूत सुविधाओं से वंचित हैं, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बाद भी ग्रामीणजन रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर हैं? क्योंकि ग्रमीणों की समस्या के समाधान के लिये ना तो अधिकारी पहल कर रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। इसी वजह से ग्रमीणों को शासकीय राशन दुकानों से खद्यान्न, कैरोसीन, शक्कर, पेयजल के साथ-साथ स्वास्थ्य जैसी आम सुविधाओं के लिये भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? ग्रामों को जोड़ने वाली सड़के जीर्णोशीर्ण अवस्था में हैं। लेकिन इनकी मरम्मत के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं, वहीं देखा जावे तो वर्तमान स्थिति में क्षेत्र के अनेक ग्रामों में हैंडपंप बिगड़ी हालत में पड़े हैं और कुछ दूषित पानी उपलव्ते हैं, जिसे ग्रामीणजनों को निस्तार के साथ साथ पीने के उपयोग में भी लाना पड़ता है, ग्राम्यांचलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये भी शाला भवन तो बन गये हैं। मगर उनमें शिक्षकों का टोटा है, शिक्षकों की कमी होने से गरीब बच्चें अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते है खैर अभी तक स्कूल बंद चल रहे है? मगर शिक्षण सत्र के दौरान देखा जाता है कि क्षेत्र की अनेक शालाओं में पदस्थ शिक्षक शिक्षिकार्ये मनमाने ढंग से अपने गृहनागर से समय बेसमय आना जाना करते है, जिसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को भी रहती है। परंतु वे जानते बूझते इस ओर ध्यान नहीं देते है जिसका परिणाम है कि क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई का स्तर गिर रहा है? वहीं शालाओं के बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन भी सिर्फ कागजो तक ही सिमित नजर आता है? जिसमें देखा जावे तो कुछ शालाओं की स्थिति इस प्रकार से रहती है

नीम हकीमों की हुकूमत के आगे प्रशासन बना उदासीन, आम लोगों की जिन्दगी से हो रही खिलवाड़

हरिभूमि न्यूज/ चीपली।

क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों इन दिनों नीम-हकीम अनाड़ी थैला छाप चिकित्सकों की हुकूमत देखने को मिल रही है, जिनके द्वारा इलाज के नाम पर रोगियों के परिजनों से जमकर चांदी काटी जा रही है। यह पल्ला अवसर नहीं है कि जब इस संबंध में संबंधित विभाग का ध्यान न दिलाया गया है, इसके पूर्व भी ग्रामीणजनों से मिली शिकायतों के अनुसार जिला प्रशासन का ध्यान देने के लिए मांग की जा चुकी है, किन्तु ऐसे कथित चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही के नाम पर परिणाम सिफर ही साबित हुए हैं। जनकारी के अनुसार क्षेत्र के ऐसे अनेक ग्रामीण अंचलों का जायजा लिया जावे तो निश्चित तौर पर एक गाँव में ऐसे आधे दर्जन से भी अधिक नीम हकीम थैला छाप



चिकित्सक मिल जावेंगे जो अवैध रूप से अपना कारोबार संचालित करते हुए धड़ल्ले से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर एक ओर शासन द्वारा नगर में क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु तो स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई है



योगदान देने से नही चूकते हैं। कुछ इसी प्रकार की सच्चाई बीते हुये गर्मी के दिनों में उस समय देखने मिली जब नगर में भीषण गर्मी के दौरान जब लोग नगर में ठंडे पानी के लिये तरसते हुये देखे जा रहे थे



खरीदी जावेगी। सरकार के इस निर्णय से जहां अन्नदाता टूटने से नही चूक पाा है। क्योंकि उसे 75 प्रतिशत मूंग का विक्रय माटी मोल दामों पर व्यापारियों के लिये करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जिन किसानों ने अपने अपने क्षेत्र के जिम्मेदारों पर भरोसा करते हुये दिल्ली तक पहुंचाने में कोई कसर नही छोड़ी गई थी वहीं किसानों के हम दर्दों द्वारा जिस तरह मूंग फसल को पहले जहरीला बताते बताने में कोई कसर नही छोड़ी गई थी और अब सरकार के निर्णय पर चुप्पी साधे जाने के कारण सदा ही किसानों के बीच अपने आपको किसान का बेटा कहलाने पर खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाने में कोई कसर नही छोड़ी गई है...? क्योंकि रात दिन एक करते हुये अपने खेतों में मेहनत करने वाले किसानों द्वारा जिस जिम्मेदारों पर भरोसा जताते हुये उन्हें दिल्ली पहुंचाया गया था और उनके द्वारा ही अब मुश्कत के दौरान अपने किसान साथियों से दूरी बनाते हुये चुप रहने से अन्नदाता अपने आपको जहां उगा हुआ महसूस करने से नही चूक रहा है। वहीं दूसरी ओर गौर किया जावे तो इस सच्चाई से निश्चित तौर से अन्नदाता की आंखों में आंसू आने से नही चूक पा रहे है। मगर कहा जाता है कि जब किसान अपनी पर आ जा जाता है तो सरकारों को झुकने के लिये मजबूर होना पड़ता है और निश्चित ही वह समय आने से नही चूकेगा और अन्नदाताओं के साथ इस तरह बेबफाई करने वालो की स्थिति ...होने से नही चूक पायेगी...? मगर किसी तरह मूंग फसल से

प्रतिबंध अवधि के बावजूद भी खुलेआम जारी है मत्स्य आखेट, नगर में कलेक्टर आदेश साबित हो रहा बेअसर

हरिभूमि न्यूज/साईंखेड़ा/गाडरवारा।

प्रतिवर्ष देखा जाता है कि 15 जून से 16 अगस्त तक के लिए नदी नालो सहित अन्य नदियों में मछली के शिकार पर जिला दंड अधिकारी द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कुछ इसी प्रकार से इस वर्ष भी जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करते हुये संपूर्ण जिले में मछली मारने से लेकर विक्रय पर प्रतिबंध आदेश तो जारी कर दिया गया है। मगर उस आदेश को पालन होते हुये कही दिखाई नही देने से यह प्रतीत होने से नही चूक पा रहा है कि शायद स्थानीय स्तर पर बैठे अधिकारियों की नजरों में जिला दंड अधिकारी का आदेश कोई महत्व नही रखता है या फिर जिला स्तर से जारी हुआ यह आदेश मात्र कागजों की खानापूर्ति करते हुये अखबरों की खबरों तक सीमित होकर रहे गया है? क्योंकि जब जिला दंड अधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है तो उसका पालन करने की जिम्मेदार अनुविभागीय अधिकारी से लेकर तहसीदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पुलिस विभाग की होती है। कुछ इसी प्रकार से मत्स्यआखेट यानि की मछली मारने व विक्रय करने के आदेश को जारी हुई पूरे कई दिनों का



समय बीत जाने के बाद भी कार्यवाही होते हुये दिखाई नही देने से जहां नगर सहित क्षेत्र की नदियों में खुलेआम मछली मारने के साथ विक्रय होते हुये देखा जा रहा है। जबकि जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में म.प्र नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 की उप धारा (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस बंद ऋतु अवधि में मत्स्यआखेट पूर्णतरु प्रतिबंधित रहेगा तथा इस अवधि में अवैधानिक मत्स्यआखेट, मत्स्य परिवहन एवं

मत्स्य क्रय, विक्रय करना पूर्णरूप से निषध रहेगा। प्रदेश शासन के मछली पालन विभाग के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नही है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया है तो उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उपरोक्त नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघन कर्ता को एक वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार से जिला कलेक्टर ने

शहर में लगे हुये बिजली खम्बों पर निजी कंपनी द्वारा अपनी लाईन डालकर किये जा रहे उपयोग से यदि कोई घटना घटित होती है तो कौन होगा जिम्मेदार?

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। शहर के मुख्य मार्गों से लेकर कालोनियों में बिजली विभाग द्वारा स्थापित किये गये विद्युत सप्लाई व्यवस्था के खम्बों पर बीते हुये लगभग दो सालों से जिस तरह निजी कंपनी द्वारा अपनी लाईन डाली गई है उसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल खड़े होने से नही चूक रहे है? इस तरह सरकारी बिजली खम्बों पर डाली जाने वाली केबिल में जियो कंपनी का मार्का अंकित होने से यह अनुमान लग रहा है कि शायद निजी कंपनी जियों द्वारा अपने संचार व्यवस्था के लिये इन सरकारी खम्बों का उपयोग किया जा रहा है? मगर बिजली विभाग द्वारा स्थापित किये गये यह खम्बे जहां शासकीय संपत्ति माने जाते है और उनका उपयोग सिर्फ बिद्युत व्यवस्था के लिये उपयोग करना बताया जाता है? मगर इसके बाद भी जिस तरह से निजी कंपनी द्वारा इन खम्बों का उपयोग करने के लिये खम्बों के ऊपर चढ़कर जहां अपनी सामग्री



फिट करते हुये उनके ऊपर अपनी केबिल डालने का कार्य किया जा रहा है इससे निश्चित तौर से नगर में विद्युत उपभोक्ताओं के लिये जहां परेशानी का सामना करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा तो दूसरी ओर निजी कंपनी द्वारा डाली जाने वाली अपनी केबिल में इतनी ढील दी जा रही है जिसके चलते नगर की कालोनियों व मुहल्लो में जब कोई संभावना से इंकार नही किया जा सकता है? वैसे भी देखा जावे तो नगर के अंदर लगे हुये बिजली खम्बों की हालत यह बनी है कि वह पहले से ही विद्युत लाईनों के चलते

मकड़ी के जाल के समान बने हुये है और उसी के ऊपर से इस नई लाईन के डाले जाने से विकट स्थिति बनने से नही चूक पा रही है तो सबाल यह पैदा हो रहा है कि यदि किसी दिन कोई घटना घटित होती है तो इसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा...? मगर इसके बाद भी खुलेआम बिजली खम्बों का निजी कंपनी द्वारा उपयोग किये जाने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों की चुप्पी निश्चित तौर से अनेक सबाल खड़े करने से नही चूक रही है? कही ऐसा तो नही कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के चलते आपसी समझौता करते हुये इन्हे शासकीय संपत्ति का उपयोग करने के लिये चूपचाप तरीके से अनुमति प्रदान कर दी गई हो? खैर सच्चाई जो भी हो उसे तो भगवान ही जाने। मगर इस तरह शासकीय संपत्ति का निजी कंपनी द्वारा उपयोग करने के साथ विद्युत सप्लाई खम्बों पर डाली जाने वाली यह लाईन नगरवासियों के लिये परेशानी का कारण साबित होने से नही चूक पायेगी।



स्वर संक्षेप

एडीपीसी का विदाई समारोह आयोजित



हरिभूमि न्यूज – नरसिंहपुर।
गर्ग दिवस विपरीत जैन एडीपीसी
रमसा एवं मोहन विश्वकर्मा प्राचार्य
अधिकांश स्थानांतरण सिवनी जिले
में होने पर उन्हें जिला शिक्षा
अधिकारी कार्यालय नरसिंहपुर द्वारा
विदाई दी गई। इस अवसर पर डॉ
अनिल कुशवाहा जिला शिक्षा
अधिकारी नरसिंहपुर ने कहा कि श्री
जैन एवं श्री विश्वकर्मा ने जिले में
बेहतर सेवाएं दी। कार्यक्रम में
राजवी केशोर श्रौराव्रत प्राचार्य
डाइट, ए एस मसमरा सहायक
संचालक, अनुज जैन जिला क्रीड़ा
अधिकारी, प्रकाश साहु मुख्या
लिपिक एवं समस्त स्टाफ
उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय पर्यटन क्विवज प्रतियोगिता हेतु आवेदन 25 तक

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश राज्य बौद्ध चीफ बोपाल के माध्यम से वर्ष 2026 में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पर्टेंटन विवेक प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्तरীয় 7 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में प्रतियोगिता में जिले के सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा तीन सहस्त्रीय एक टीम के रूप में प्रतियोगिता में सहभागिता की जाएगी। प्रतियोगिता में सहभागिता सुनिश्चित करके के लिए प्रतिभागिता के विद्यार्थी का पंजीयन एक जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, जिसको अंतिम तिथि 25 जुलाई 2026 नियत की गई है। प्रतिभागिता के विद्यार्थी अपना पंजीयन में जाकर कर सकते हैं।

कलेक्टर ने किया पौधरोपण व विकास कार्यों का निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने जिले में पौधरोपण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पौधरोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान सीसीओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी उदय प्रताप सिंह, परियोजना अधिकारी विपिन लाड सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर श्रीमती सिंह, अधिकारियों व नागरिकों ने ग्राम पंचायत धुबधरागोड़ी में विभिन्न प्रजातियों के नौबू, आम, पाकड़, पीपल एवं औंवला सहित करीब 100 पौधों का रोपण किया गया। कलेक्टर ने कट्टर टूट एवं ग्राम के पारंपरिक तालाब का निरीक्षण कर तालाब का गहरीकरण करने, पडल निर्माण कराने तथा अतिक्रमण हटाने वृहद स्तर पर पौधरोपण कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शेड नदी के कटाव को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंधन करने और बांस का रोपण करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत खमरिया-जरजोला के खपड़ी गांव स्थित शांतिधाम परिसर में पौधरोपण एवं गैप फिलिंग का कार्य किया गया। कलेक्टर ने परिसर की बाउंड्रीवाल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन 47 लाख रुपये लागत के सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत खापा के ग्राम मेहका में सीसी सड़क एवं शांतिधाम परिसर



में तार फेंसिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने ग्राम पंचायत करहैया- नर्मदा में नर्मदा समृद्धि परियोजना के अंतर्गत लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत पौधरोपण कार्य का

निरीक्षण किया। नर्मदा आश्रय स्थल पर विभिन्न प्रजातियों के करीब 100 पौधे लगाए गए। यहां निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निरीक्षण के दौरान समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पदयात्रा निकालकर दिया वृक्षारोपण का संदेश- नीम के बीजों का किया रोपण



तैदूखड़ा। रविवार को नगर की योगदान सेवा समिति के द्वारा तैदूखड़ा से इमझिरा के बीच पैदल यात्रा निकालकर लोगों को वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए सड़क मार्ग के किनारे नीम के बीज का रोपण किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित समिति के सदस्यों के द्वारा सड़क मार्ग के दोनों तरफ नीम के बीजों को रोपित किया गया। सदस्यों का मानना है कि उक्त बीज अंकुरित होकर स्वयं पौधे का आकार लगे फिर इनकी परवरिश स्वयं सदस्य तो करेंगे ही वहीं सड़क किनारे खेत-मैदान को भी इसमें रोपण लिया जाएगा। गौरलाल रहे कि उक्त समिति के द्वारा हर साल अलग अलग क्षेत्रों सड़क मार्गों पर छायादार फलदार पौधे रोपण किया जाता है जिनमें सैकड़ों पौधों ने वृक्ष का रूप ले लिया है। जो राहगीरों को छाया प्रदान करने के साथ फल और मुफ्त में आकसीजन प्रदान कर रहे हैं। योगदान समिति की इस पहल का सभी वर्गों द्वारा सराजाना की जा रही है।

निर्मल ग्रामों की बर्बादी, कमीशन की आड़ में आंखे बंद किये हुए अधिकारी?

हरिभूमि न्यूज/सालीचौका।
अग्रेष को विकास और समृद्धि की ओर
देखकर करने के लिए चलाई जा रही
योजनाओं के नेहत गांव को साफ
सुधरा और हैरा भरा बनाने की
कवायद में है और इसके लिए शासन
प्रशासन निर्मल ग्राम बनाने के लिए
हरि संभव प्रयास कर रहा है, इसके
लिए समय समय पर गांव को
चायनित कर खर्च पर लाखों करोड़ों
रुपये की राशि खर्च की जा रही है
जिसमें गांव के प्रत्येक परिवारों के
घरों में शौचालय बनाये गये है। वहीं
सड़क और पक्की नालियां
सड़क और कुडादान व जल न्छौतों
को साफ सुधरा बनाया जाना है और

इसकी देख रेख के लिए जिला स्तर पर हर निकास में अलग से कमजोरी भी बनाकर किये गये हैं जिन्हें वेतन के रूप में मोटी रकम और भ्रमण करने के लिए वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। लेकिन यहाँ अधिकारी कमजोरी आफिसों में बैठे बैठे ही योजना का संचालन कर रहे हैं और इसका परिणाम यह देखने में आ रहा है कि गाँवों में बनायी गई सड़कें एक चंद वर्षों में ही पूरी तरह उखड़ चुकी हैं, वहीं पूर्व के समय में गाँवों में बनाये गये शौचालयों की स्थिति भी इसी प्रकार से देखने में मिल रही है कि वह कारको एवं कूड़ादानों में तब्दील हो गये हैं। तो हजारों रुपया की लागत से

बिना नम्बर के चल रहे सैकेडों टैक्टर से दर्यटना की बनी आशंका

नादनेर/गाडरवावा। जहां एको प्रशासन द्वारा क्षेत्र के अनेक जहांहर पर चौकिया पय है, मगर इसको बाद भी जहां प्रको से प्रशासन द्वारा ऐसे वानेको को मजर अंदाज किया जय रहे है, जिन्सने प्रत्येक रूप से देखा जयने तो देवटर द्वारा मेरे वाने, गुज्म का अयेक उखनल ल विभाग द्वारा इस ओर कार्यावां की जा रही है, वही अयेक उखनल करने वाले अयेक जने देवटर को उपयोग में ला रहे है जिन्सने नमस्तर नही लिखा हुआ है, इस प्रकार से बर्बर मन ओकर एक तरफ राजस्व को लाखों का गुनसान हो रहे है। वही इस पर अभी तक आर टी ओ को देखा जयने कारा इन देवटर वालों को हीसने बुन्द है, क्षेत्र को सड़कों पर इस प्रकार से सेवक देखा जयने तो अधिकतर अयेक उखनल के कार्य में सलियत है।

बनाये गये कचरा घर टूट गये है, जलाश्रयों के समीप ही घासे एवं दलदल निर्मित हो गयी है, इसके बावजूद शासन द्वारा इन निर्मल ग्रामों को पुरस्कार द्वारा नवाजा गया है, जिसमें लाखों रूपये को इनम राशि को सरपंच सचिवों ने डकार ली? यदि इन गांवों को सच्चाई पर गौर किया जावे तो अनेक पंचायतों तो इस प्रकार की जहज पर लोग आज भी शौच के लिए बाहर जाते हुए नजर आते है और दूसरी ओर सड़कों को गुमवात को रक्षितार करते हुए कमीशन की आड़ में अधिकारियों द्वारा उन्हें पास कर दिया गया है जो चंद दिनों के बाद भी टूटा टूटा शुरू हो चुकी है

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित, विद्यार्थियों को दी जानकारी

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। विगत दिवस जिले के अग्रणी महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद शास. स्नात. महाविद्यालय में सत्र प्रारम्भ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस हेतु उच्च शिक्षा म.प्र. शासन द्वारा निर्देशित किया गया था कि दीक्षारम्भ समारोह आयोजित किया जाये ताकि नव प्रवेशित छात्र-छात्राएँ अपनी संस्थाओं से उनकी शैक्षणिक प्रक्रियाओं से एवं शासन की प्रदत्त सुविधाओं से परिचित हो सकें।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सर्सेस का दर्जा प्राप्त स्वामी विवेकानंद पी.जी. महाविद्यालय नरसिंहपुर क्षेत्र का अग्रणी कॉलेज है, अतः इस महाविद्यालय में म.प्र. शासन ने अनेक विषयों के साथ अध्ययन में नवाचार जोड़ा है। हेतु अधोसंरचना तैयार की गई है। शिक्षण हेतु इंटरैक्टिव पैनल, प्रोजेक्टर, डिजिटल लाबोरी को समाहित करते हुए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को अध्ययन में जोड़ा है। कार्यक्रम में दिनांक 01 जुलाई से 03 जुलाई तक तीन दिवसीय कार्यक्रम को प्राचार्य डॉ. आर.बी. सिंह के मार्गदर्शन में



अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नई शिक्षा नीति एवं सत्रीय शैक्षणिक गतिविधियों का परिचय डॉ. गणेश कुमार सोनी विभागाध्यक्ष गणित द्वारा दिया गया। प्रो. आलोक तिवारी द्वारा महाविद्यालय का परिचय एवं महाविद्यालयीन समितियों का परिचय दिया गया। प्रथम दिवस महाविद्यालय के परिसर भ्रमण हेतु प्रो. शोभा मिश्रा द्वारा विभिन्न विभागों, लाइब्रेरी सहित परिसर से परिचित किया गया। तृतीय दिवस डॉ. स्वाति चांदेकर विभागाध्यक्ष अंग्रेजी, संतोष अवस्था एवं डॉ. अभयराज साहू (कम्प्यूटर विभाग) द्वारा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के संबोधित करके हुए विषयों के चयन

महाविद्यालय में विभिन्न एम.डी.सी. एवं रोजगारी-मुखी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। साथ ही छात्र-छात्राओं को कक्षाओं में अधिक उपस्थिति के साथ नियमित अध्यापन से जुड़ने निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय परिसर में विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत विशाल मुख्य भवन, नवीन प्रयोगशाला भवन एवं छात्रावास की सुविधा इस नवीन सत्र में प्रारम्भ हो रहा है। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन प्रो. गजेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया डॉ. अमित कुमार ताम्रकार एवं डॉ. गगन कुमार ताम्रकार, डॉ. शिवानी शिवहरे द्वारा संचालित की जा रही है।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु शिविर 8 से

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर | 8 जुलाई को जिले के नगर पालिका गाडरवारा के गांधी वार्ड व राजेन्द्र बाबू वार्ड, नगर पालिका नरसिंहपुर के नेहरू वार्ड व शंकर वार्ड, नगर पालिका करेली के अम्बेडकर वार्ड व गणेश वार्ड, नगर पालिका गोटेगांव के आजाद वार्ड व बजरंग वार्ड, नगर परिषद तेंदुखेड़ा के वार्ड एक भगत सिंह वार्ड व वार्ड दो बाल गंगाधर तिलक वार्ड, नगर परिषद चीचली, नगर परिषद सालीचका और नगर परिषद सांईखेड़ा के वार्ड एक व वार्ड दो में शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरह 8 जुलाई को जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत अम्हेटा, अमागांवबड़ा, अमथनू, बघुवार व बम्हनी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत आलोद, अमोदा, बबरिया, बचई व बडगुवा, जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत आड़ेगांव, जमाड़ा, अर्जुनागांव, बाबाईकला व बाबई खुर्द, जनपद पंचायत गोटेगांव की ग्राम पंचायत अकोला, आंखीवाड़ा, अतरिया, बढैयाखेड़ा व बगासपुर, जनपद पंचायत सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत आड़ेगांव, अजंद, अमागांव व डोटा, बगदरी व बम्हरी और जनपद पंचायत सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत अजंसरा, अडिया, अट्टाइसा, बम्हरी व बंभ में शिविर लगाए जाएंगे। जारी आदेश के मुताबिक शिविर के दौरान प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा, जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम होनी चाहिए। उक्त पंजीयन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा। साथ ही संबल कार्ड एवं सनिमांग कर्मकार मंडल कार्ड के लंबित आवेदनों का पंजीयन भी किया जाएगा। शिविर के दौरान नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों का शत प्रतिशत ई-केवयसी की जाएगा। डुप्लीकेट, मृतक व स्थायी पलायन कर चुके व्यक्तियों के नाम काटे जाएंगे। पटवारी के माध्यम से किसानों का यूनिफ फार्म आर्डर्ड के तहत फार्मर पंजीयन किया जाएगा। आधार कार्ड में आवश्यक सुधार (अपडेशन) का कार्य पोस्टमैन के माध्यम से किया जाएगा। आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आयुभ्रमन कार्ड बनाए जाएंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित आजीविका मिशन के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के फार्म भरवाए जाएंगे। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जिले में सभी गतिविधियों के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका नगर परिषद अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

ई-केवायसी हेतु शिविर होंगे आयोजित

नरसिम्ह नृप - नरसिंहपुर । जिले में विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों से कोटि हलाहारी वगैरह ने ही तथा विभिन्न योजनाओं के द्वारा विहाहारीयों के भी केवयसीयों में अमल भी केवयसीयों ललित न रह, इसके लिए कलेक्टर श्रीमती नरणी रजिह के आदेश पर जिले में हैहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्डों आगे वामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के एक दिन पूर्ण शहरी क्षेत्र में वर्ड प्रमारी, आशा कार्यकर्ता व आंगनवाडी कार्यकर्ता वर्ड अमण कर और पंचायतों में सचिव, ग्राम रोजनगर सचिव, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता व पंचायी ग्राम अमण कर वर्डित परिवारों से सम्पर्क कर आवश्यक दस्तावेज शिविर में आने के लिए आगार करेगा। शिविर दिवस को वर्डित परिवारों की आवश्यक पंजीकरण सेवुकेनरु ग्राम पर पूर्ण किया जाएगा। शिविर की जानकारी नगरिकों को वह दिवस पूर्ण वर्डित पौटकर या लाउड स्पीकर के माध्यम से दी जाएगी।

भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन सम्पन्न

राष्ट्रनिष्ठा और कुशल नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण डॉ. मुखर्जी: मंत्री श्री पटेल



हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। रविवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केबिनेट मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल एवं जिलाध्यक्ष रामप्तेन्ही पाठक, जिला प्रभारी शरद जैन, पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल, विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, महन्त नागेश प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा उदय प्रताप कौरव, मीडिया संयोजक स्मृति जैन, हाकम सिंह चढ़ार, महंत प्रीतम पुरी की उपस्थिति में दीप प्रचलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसमें सर्वप्रथम भाजपा जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए बताया कि भारत की एकता अखण्डता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रखर प्रहरी महान शिक्षाविद् राष्ट्रावदी चिन्तक एवं जनसंघ के संस्थापक श्रेष्ठ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रसेवा, त्याग और दृढ़संकल्प का अनुपम उदाहरण है उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से स्वतंत्र भारत की राजनीति को नई दिशा प्रदान की है तथा राष्ट्रहित की भावना को संदेव सर्वोपरि रखा है।

आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत

श्री पाठक ने कहा कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंति केवल उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण करने का अवसर नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति एवं स्वशासन सांस्कृतिक चेतना एवं अखण्ड भारत के



उन्ने आदर्शों को आत्मसात करने का प्रयत्न अवसर पर ही। तेन्दुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह से पहले ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के जीवन पत्र प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की एवं उसके संस्थापक के रूप में अपना बेहतर योगदान देते हुए जनसंघ को देश में एक सशक्त राष्ट्रवादी राजनैतिक विकल्प के रूप में पहचान दिलाई। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य संस्कृतिक अस्मिता लोकतांत्रिक मूल्यों राष्ट्रवादा और अखंड भारत की भावना को सशक्त करना था। भारतीय जनता पार्टी जो आज देश की प्रमुख राजनैतिक शक्ति है उसमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान अतुलनीय है। उनका योगदान केवल एक राजनैतिक दल की स्थापना तक सीमित नहीं

रहा बल्कि उन्होंने भारत की राष्ट्रवादी नीति को एक स्थाई वैचारिक आधार प्रदान किया।

राष्ट्र निर्माण में डॉ. मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान

मन्त्री प्रहलाद सिंह डटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति को अब महान रास्ता निर्माताओं में डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम मुख्य रूप से आता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक नीतियों और औद्योगिक विकास को दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय परिषद में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले डॉ.मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में देश को औद्योगिक



आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण पहल की। जब देश स्वतंत्रता के बाद आर्थिक चुनौतियों संसाधनों की कमी और औद्योगिक पिछड़े पन से जूझ रहा था। ऐसे समय में डॉ. मुखर्जी ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया। केन्द्रीय मंत्री मंडल महत्वपूर्ण सदस्य होने के बाद भी राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर उन्होंने कर्षण समझौता नहीं किया।

राष्ट्रहित में अमूल्य योगदान

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि 1950 में उन्होने नेहरू लियाकत समझौता में अपनी असहमति दर्ज कराते हुए अपने सिद्धांतों एवं राष्ट्रहित के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण देते

हुए केन्द्रीय मंत्री मंडल से अपना स्वीका दे दिया। आज उनकी जयंती पर राष्ट्र उन्हें ऐसे दूरदर्शी नेता के रूप में स्मरण करता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के उद्योगिक विकास राष्ट्रीय एकता और स्वभिमान को नई दिशा देने में अपना अमूल्य योगदान दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विधायक मीडियन प्रभारी वैभव नेमा ने बताया कि मंच का संचालन जिला महामंत्री राहुल कौरव एवं आभार जिला उपाध्यक्ष मुकेश भैया ने किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला प्रचायत उपाध्यक्ष सदस्य गण नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष एवं मंडल महामंत्री गण पाषंद, सरचंद्र, जनपद संस्थ, एवं जिले की चारों विधानसभाओं से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपना सहभागिता दी।